सवाल-जवाब अविनाश वर्मा, महानिदेशक, इस्मा

'कुछ समय गिरेंगी चीनी की कीमतें'

कई महीनों के इंतजार के बाद सरकार ने आखिरकार लेवी चीनी प्रणाली और शक्कर जारी करने की व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। इससे 80,000 करोड़ रुपये का भारतीय चीनी उद्योग नियंत्रण मुक्त हो जाएगा। बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ विशेष बातचीत में भारतीय चीनी उद्योग की प्रमुख संस्था इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि इन उपायों से कुछ समय तक चीनी की खुदरा कीमतों में गिरावट आएगी। उनसे बातचीत के अंश :

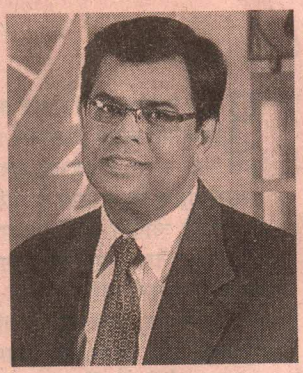

आप यह कैसे मानते हैं कि लेवी चीनी और कोटा प्रणाली खत्म करने से चीनी उद्योग को फायदा होगा?

नियंत्रित रिलीज प्रणाली खत्म करने से मिलों को व्यावसायिक लाभ के लिए चीनी बेचने की आजादी मिलेगी। वे नकदी की बेहतर योजना बना सकेंगी और चीनी का स्टॉक, ब्याज का बोझ और लागत घटा सकेंगी। इसी तरह अपनी लागत के करीब 60 फीसदी पर लेवी चीनी आपूर्ति करने का बोझ हटने से हर वर्ष उद्योग के घाटे में 3000 करोड़ रुपये तक की कमी आएगी। इन फैसलों से उद्योग को 20-25 फीसदी की संभावित वार्षिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी।

आम धारणा है कि लेवी चीनी खत्म करने से चीनी की खुदरा कीमतें बढ़ेंगी। इस पर क्या कहेंगे आप?

इस फैसले के बाद शुरुआत में मिलें बैंकों और किसानों को भुगतान के लिए ज्यादा चीनी की बिक्री करेंगी, जिससे चीनी कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। गन्ने का बकाया 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। इसलिए कुछ समय चीनी की कीमतों में गिरावट आ सकती है और इसके बाद उत्पादन लागत वसूलने के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है कि लागत में कमी के फायदे का एक भाग उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है।

इस फैसले से किसानों को किस तरह फायदा होगा?

नकदी प्रवाह के बेहतर प्रबंधन से मिलें किसानों को समय से भुगतान करने की स्थिति में होंगी। इससे गन्ने की बकाया राशि नियंत्रण में रहेगी। मिलों पर लेवी चीनी की बाध्यता खत्म होने और लागत घटने से उनको होने वाले फायदे से किसानों को भी गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी। सरकार के फैसले से मिलों और कृषि दोनों में ज्यादा निवेश होगा, जिससे किसानों को उत्पादकता सुधारने में मदद मिलेगी और उनकी आय में भी इजाफा होगा।

आपके मुताबिक चीनी क्षेत्र में और किन सुधारों की जरूरत है?

अगला कदम गन्ने की क़ीमतों को तर्कसंगत बनाना होगा, जिसकी सिफारिश रंजराजन समिति ने भी की है। गन्ना कीमत और चीनी की मिलने वाली कीमत के बीच तालमेल होना चाहिए। यह व्यवस्था दुनियाभर में है। इससे चीनी उत्पादन में उतार-चढ़ाव कम होगा। किसानों और उद्योग को भी स्थायी फायदा मिलेगा।

बिजनेस स्टैंडर्ड
6/4/13